विनीत कुमार और अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 577/2017)

31 मार्च, 2017

[ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा482 - को रद्द करना - शिकायतकर्ता, उसके पति और उसके बेटे ने आरोपी व्यक्तियों से कुछ राशि उधार ली थी-अभियुक्तों को पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए. विभिन्न चेक निकाले गए थे, जिनका अपमान किया गया था-जिसके बाद शिकायतें आई थीं। अभियुक्त द्वारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम दायर किया गया-इसके बाद, शिकायतकर्ता ने अभियुक्त पर अपने घर पर बलात्कार का आरोप लगाया और आवेदन दायर किया। 156 (3) मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता-जाँच के दौरान, आई. ओ. ने अभियोजक/शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया। 164 सी. आर. पी. सी. और अन्य सामग्रियों पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की-लेकिन, मजिस्ट्रेट ने आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार पाया और आरोपी को तलब किया-आदेश के खिलाफ आरोपी द्वारा दायर संशोधन को खारिज कर दिया गया-उच्च न्यायालय ने भी आवेदन को खारिज कर दिया। 482 दंड प्रक्रिया संहिता-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः घटना की तारीख को शिकायतकर्ता की कोई चिकित्सा जांच नहीं की गई थी-यह लगभग एक महीने के बाद किया गया था, जो पूरी तरह से अप्रासंगिक था-इसके अलावा, शिकायतकर्ता के बहनोई और साली ने अपने बयान दर्ज किए कि शिकायतकर्ता ने एक झूठी रिपोर्ट दर्ज की थी-जांच अधिकारी को भी अपराध का कोई

सबूत नहीं मिला-शिकायतकर्ता के गंजे दावे के अलावा कि सभी अभियुक्तों ने उसके साथ बलात्कार किया था, ऐसा कुछ भी नहीं था जो अदालतों को आरोपी के खिलाफ राय बनाने के लिए प्रेरित कर सकता था-सामग्री से संकेत मिलता है कि आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से शुरू किया गया था-इसलिए, उच्च न्यायालय के फैसले के साथ-साथ निचली अदालतों द्वारा पारित आदेशों सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया-दंड संहिता, 1860-धारा 45 376 (डी), 323

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 482-उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ-अभिनिर्धारितः यदि किसी व्यक्ति द्वारा अप्रत्यक्ष उद्देश्य से न्यायालय की गंभीर प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का प्रयास किया जाता है, तो न्यायालय को प्रयास को बहुत हद तक विफल करना होगा-यदि मामला हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल के मामले में स्पष्ट रूप से उल्लिखित श्रेणियों में से किसी एक में आता है, तो न्यायालय अभियोजन चलाने की अनुमति नहीं दे सकता है-न्यायिक प्रक्रिया को संचालन या उत्पीड़न के साधन में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है-न्याय प्रशासन।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1. अभिलेख पर यह इंगित करने के लिए पर्याप्त सामग्री थी कि अभियुक्त और शिकायतकर्ता, उसके पति और बेटे के बीच वित्तीय लेनदेन हुए थे। शिकायत के पति और बेटे द्वारा जारी किए गए चेक के अनादर पर, अभियुक्त द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी गई थी। शिकायतकर्ता के परिवार के सभी सदस्य एक ही घर में रह रहे थे। जाँच के दौरान, आई. ओ. ने शिकायतकर्ता के पति के भाई के साथ-साथ पति के भाई की पत्नी के बयान दर्ज किए हैं जो एक ही घर में रह रहे थे और स्पष्ट रूप से इनकार किया है कि

उनके घर में कोई घटना हुई थी। दोनों ने अपने बयानों और हलफनामों में शिकायतकर्ता की झूठी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए निंदा की है। उनके बयान केस डायरी का हिस्सा थे और ऐसी सामग्री थी जिस पर गौर किया जाना चाहिए था जिसे आई. ओ. द्वारा अंतिम रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। [पारस 28,34) [940-सी; 941-बी-डी)

2. तथ्य यह है कि घटना के दिन या अगले दिन या 07.11.2015 पर भी कोई चिकित्सा जांच नहीं की गई थी, जब आई ओ ने शिकायतकर्ता और उसके पति को चिकित्सा जांच कराने के लिए कहा था। इसके बाद इसे 20.11.2015 पर किया गया, जो पूरी तरह से अप्रासंगिक था। शिकायतकर्ता के गंजे दावों के अलावा कि सभी अभियुक्तों ने बलात्कार किया है, ऐसा कुछ भी नहीं था जो अदालतों को यह राय बनाने के लिए प्रेरित कर सके कि वर्तमान मामला अभियोजन के मामले के लिए उपयुक्त है जिसे शुरू किया जाना चाहिए। इसके अलावा, धारा 164 Cr.P.C के तहत अभियोजक/शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए बयान को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन बयान पर पूर्ववृत्त, तथ्यों और परिस्थितियों के साथ विचार करने की आवश्यकता थी जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। [पैरा 35] [941-डी-एफ)

3. ऐसे मामले हैं जहां अभियोजक द्वारा धारा 164 Cr.P.C के तहत बयान के बावजूद उच्चतम न्यायालय ने जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री का उल्लेख करते हुए कहा था कि मामला उपयुक्त था जहां उच्च न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना चाहिए था। [पैरा 38) [944-ई)

4. धारा 482 Cr.P.C के तहत उच्च न्यायालय को दी गई अंतर्निहित शक्ति न्याय की प्रगति के उद्देश्य और उद्देश्य के साथ है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अप्रत्यक्ष उद्देश्य से न्यायालय की गंभीर प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की कोशिश की

जाती है, तो न्यायालय को इस प्रयास को बहुत हद तक विफल करना होगा। न्यायालय अभियोजन को जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकता है यदि मामला हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल न्यायिक प्रक्रिया में इस न्यायालय द्वारा सचित्र रूप से उल्लिखित श्रेणियों में से किसी एक में आता है जो एक गंभीर कार्यवाही है जिसे संचालन या उत्पीड़न के साधन में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जब यह इंगित करने के लिए सामग्री है कि एक आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से की जाती है और कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से एक गुप्त उद्देश्य के साथ शुरू की जाती है, तो उच्च न्यायालय धारा 482 Cr.P.C के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में संकोच नहीं करेगा। (7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से देखा जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे रोकने के उद्देश्य से शुरू की जाती है। उपरोक्त श्रेणी 7 वर्तमान मामले के तथ्यों में स्पष्ट रूप से आकर्षित है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल के फैसले को नोट किया है, लेकिन वर्तमान मामले के प्रासंगिक तथ्यों का विज्ञापन नहीं किया है, जिन सामग्रियों पर आई. ओ. द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस प्रकार, वर्तमान एक उपयुक्त मामला है जहाँ उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए था। पी. सी. और आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। [पैरा 39] (944-एफएच; 945-बी-सी]

*हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य 1992 सुपी। (1) एस. सी. सी. 335.:. पर निर्भर।

कर्नाटक राज्य बनाम एल. मुनिस्वामी और अन्य 1977 (2) एस. सी. सी. 699: [1977) 3 एस. सी. आर. 113; कर्नाटक राज्य बनाम एम. देवेंद्रप्पा और आमः 2002 (3) एस. सी. सी. 89: (2002) 1 एस. सी. आर. 275; सुंदर बाबू और अन्य।

बनाम तमिलनाडु राज्य 2009 (14) एस. सी. सी. 244; प्रिया व्रत सिंह और अन्य। बनाम श्याम जी सहाय 2008 (8) एस. सी. सी. 232: [2008] 11 एस. सी. आर. 897; प्रशांत भारती बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) 2013 (9) एस. सी. सी. 293: [2013] 1 एस. सी. आर. 504-संदर्भित

मामला कानून संदर्भ

[1977) 3 एस. सी. आर. 113 पैरा 21 (1992) पूरक के लिए संदर्भित है। 1 सेकण्ड 335 पैरा 22 [2002) 1 एस. सी. आर. 275 पैरा 23 120091 14 सेकण्ड 244 पैरा 24 [2008] 11 एस. सी. आर. 897 पैरा 25 [2013) 1 एस. सी. आर. 504 पैरा 35.

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 577/2017

2016 की धारा 482 सं. 34752 के अधीन आवेदन में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक न्यायालय के दिनांकित निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों के लिए अधिवक्ता जयंत के. सूद, हनी खन्ना, करुणाकर महालिक, अजय पी. तुशीर, सुश्री रूमी चंदना।

प्रत्यर्थियों के लिए अधिवक्ता अनिल कुमार, नरहरि सिंह।

न्यायालय का निर्णय अशोक भूषण, जे. द्वारा दिया गया।

1. यह अपील इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के धारा 482 Cr.P.C के तहत अपीलार्थियों द्वारा दायर आवेदन को खारिज करने के फैसले के खिलाफ दायर की गई है। अपीलार्थियों ने धारा 482 Cr.P.C के तहत आवेदन दायर किया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-एन, मुरादाबाद द्वारा अपीलार्थियों को आई. पी. सी. की धारा 452,376 (डी) और 323 के तहत अपराध के लिए समन करने के साथ-साथ जिला सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए अपीलार्थियों द्वारा

दायर आपराधिक संशोधन को खारिज करते हुए। इसके बाद अपीलार्थियों को अभियुक्त और प्रतिवादी संख्या 2 को शिकायतकर्ता के रूप में संदर्भित किया जाएगा। इस अपील में उठाए गए मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए अभिलेखों से सामने आए मामले के तथ्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है

2. अभियुक्तों ने शिकायतकर्ता श्रीमती रेखा रानी के साथ कई वित्तीय लेनदेन किए हैं। मई, 2015 के महीनों में रेखा रानी, उनके पति, अखिलेश कुमार और उनके बेटे, अंकुर। अभियुक्त No.-3 ने शिकायतकर्ता के पति और बेटे को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए 9 लाख रुपये दिए। अभियुक्त नं. 1 द्वारा शिकायतकर्ता और उसके पति को नकद में 7 लाख 50 हजार रुपये की राशि दी गई। इसके अलावा, शिकायतकर्ता के पति को आरोपी नंबर 1 से 3 लाख 60 हजार रुपये नकद और 2 लाख 40 हजार रुपये चेक द्वारा प्राप्त हुए।

3. शिकायतकर्ता के पति और आरोपी नंबर 1 द्वारा दिनांकित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें 3 लाख 60 हजार रुपये नकद और 2 लाख 40 हजार रुपये चेक के रूप में दिए गए थे। पुनः भुगतान सुनिश्चित करने के लिए शिकायतकर्ता के पति ने आरोपी नंबर 1 को 6 लाख रुपये का चेक सौंपा। शिकायतकर्ता और आरोपी नंबर 1 के बीच एक अन्य समझौता 01.06.2015 पर किया गया था जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि शिकायतकर्ता और उसके पति ने आर लिया थाः एस. अभियुक्त नं. 1 से 7 लाख 50 हजार नकद। इससे पहले शिकायतकर्ता के पति ने आरोपी नंबर 1 से 6 लाख रुपये लिए थे। पार्टियों ने कुछ शर्तों के साथ एक समझौता किया। तीसरा समझौता शिकायतकर्ता के बेटे और आरोपी नंबर 1 के बीच 31.08.2015 पर किया गया था जिसमें शिकायतकर्ता के बेटे ने स्वीकार किया कि उसके माता-पिता ने रुपये की राशि ली है। 14 लाख 50 हजार। शिकायतकर्ता और उसके पति ने आरोपी द्वारा दी गई राशि की वसूली के लिए प्रथम बैंक, कांत शाखा, जिला मुरादाबाद पर खींचे

गए आरोपी नंबर 1 को 6 लाख रुपये और 8 लाख 50 हजार रुपये के चेक दिए। समझौते में देखा गया कि राशि को वापस करने के वादे के साथ उधार लिया गया था। समझौतों को गैर-न्यायिक डाक टिकट पत्रों पर लिखा गया था जो पंजीकृत नहीं थे लेकिन उनमें उल्लिखित पक्षों के हस्ताक्षर थे।

4. अभियुक्त संख्या 3 ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायतकर्ता के पति और बेटे के खिलाफ इस आरोप के साथ शिकायत दर्ज की कि 9 लाख रुपये की राशि का भुगतान विरोधी पक्षों को किया गया था जिन्होंने इस आश्वासन के साथ 9 लाख रुपये का चेक जारी किया था कि राशि का भुगतान 22.08.2016 द्वारा किया जाएगा। शिकायत में आरोपी संख्या 3 द्वारा कहा गया था कि समय बीतने के बाद जब राशि का भुगतान नहीं किया गया था, तो चेक जमा कर दिया गया था जिसे बैंक द्वारा "पर्याप्त शेष राशि नहीं" टिप्पणी के साथ वापस कर दिया गया था। जब इस संबंध में विरोधी पक्षों से संपर्क किया गया तो विरोधी पक्षों ने उनसे कहा कि वे उनके पास न आएं। 05.09.2016 पर नोटिस देने के बाद, 21.09.2015 पर शिकायत दर्ज की गई। अभियुक्त संख्या 1 ने शिकायतकर्ता, उसके पति और बेटे के खिलाफ धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत 29.09.2015 पर एक आवेदन भी दायर किया था। शिकायतकर्ता के बेटे द्वारा आरोपी नंबर 2 को दिए गए 6 लाख रुपये के चेक का भी अपमान किया गया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत आरोपी नंबर 1 द्वारा दायर शिकायत को शिकायत No.3280/2015 के रूप में दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता, उसके पति और बेटे के खिलाफ सितंबर, 2015 के महीने में चेक का अपमान करने और शिकायतकर्ता और उसके पति और बेटे को दी गई राशि का भुगतान नहीं करने की शिकायत दर्ज की गई थी

5. 30.10.2015 पर शिकायतकर्ता ने आईपीसी की धारा 376 (डी), 323 और 452 के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए तीनों अभियुक्तों के खिलाफ धारा

156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन दायर किया। आवेदन में आरोपी के खिलाफ आरोप लगाया गया था कि आई. डी. 1 पर शाम करीब 7:30 बजे तीनों आरोपी शिकायतकर्ता के घर आए थे। उस समय वह घर में अकेली थी। यह आरोप लगाया गया कि तीनों अभियुक्तों ने उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे लाठी, मुट्ठी और लात से पीटा। इसके बाद आरोपी विनीत और नितेंद्र ने उसके साथ एक-एक करके बलात्कार किया, जबकि सोनू कमरे के बाहर खड़ा था। जब सोनू ने उन्हें शिकायत के पति के आने के बारे में बताया, तो तीनों आरोपी भाग गए। यह भी आरोप लगाया गया कि वह उसी दिन पुलिस स्टेशन गई लेकिन पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-IV, मुरादाबाद द्वारा संबंधित पुलिस स्टेशन में पंजीकरण और जांच के लिए दिनांक 03.11.2015 का आदेश पारित किया गया था। 06.11.2015 पर, अभियुक्त के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 376 (डी), 323,452 के तहत पुलिस स्टेशन कांत, जिला मुरादाबाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट No.251/2015 दर्ज की गई थी। मामला दर्ज होने के बाद जांच अधिकारी (आई. ओ.) द्वारा अपराध की जांच की गई। आई. ओ. ने शिकायतकर्ता, उसके पति और सास के बयान दर्ज किए। शिकायतकर्ता ने अपने बयान में अपने आरोप को दोहराया। यह आगे कहा गया कि वह अपने पति के साथ पुलिस स्टेशन गई लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। अगले दिन, वह अपने पति के साथ चिकित्सा जांच के लिए मुरादाबाद के सरकारी अस्पताल गई। डॉक्टर ने बाहरी चोटों की चिकित्सा जांच की लेकिन उसकी आंतरिक जांच से इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता के पति और ससुर ने भी बयान दर्ज कराए। उन्होंने बताया कि उनके घर पहुंचने से पहले ही आरोपी भाग चुके थे। आई. ओ. ने शिकायतकर्ता से पूछा कि "क्या अब वह चिकित्सा जांच के लिए तैयार है", शिकायतकर्ता के पति ने जवाब दिया, "नहीं, अब चिकित्सा जांच से कोई लाभ नहीं है। अब, मैं अपनी पत्नी की चिकित्सा जांच नहीं कराना चाहता क्योंकि बहुत समय बीत चुका है।" जब पति से पत्नी की

चिकित्सकीय जांच कराने के लिए कुछ सवाल पूछे गए तो पति ने निम्नलिखित जवाब दिएः

"प्रश्न-अब घंटे की पत्नी की चिकित्सकीय जाँच कराएँ ताकि डी. एन. ए. आदि कार्यवाही की जा सके?

उत्तर-यह घटना 22.10.2015 शाम को 19.30 बजे की है और तब से अब तक मैंने अपनी पत्नी के साथ कई बार यौन संबंध भी बनाए हैं। इस प्रकार, अब चिकित्सा परीक्षण से कोई लाभ नहीं है और इसके बजाय मैं स्वयं सकारात्मक रहूंगा।"

6. आई. ओ. के सामने, शिकायतकर्ता, उसके पति, ससुर और सास सभी ने कहा कि घटना के समय बिजली नहीं थी।

7. अभियुक्त ने अभियुक्त के दावे के समर्थन में विभिन्न व्यक्तियों का बयान भी दर्ज किया कि शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाए जाने के समय वे मौजूद नहीं थे और रात 9 बजे तक वे दशहरा मेले में अपने दोस्तों के साथ थे; आई. ओ. ने कुछ व्यक्तियों का बयान दर्ज किया जिन्होंने कहा कि अभियुक्त रात 9 बजे तक उनके साथ थे।

8. हालाँकि, शिकायतकर्ता और उसके पति ने आई. ओ. द्वारा 07.11.2015 पर पूछे जाने पर चिकित्सा जांच से इनकार कर दिया, लेकिन उसने 20 पर अपनी चिकित्सा जांच कराई। आई 1.2015। पैथोलॉजी रिपोर्ट (पेपर बुक के पेज 50 पर दायर) में कहा गया हैः "कोई भी जीवित या मृत शुक्राणु सीलबंद लिफाफे के भीतर प्राप्त धब्बों को नहीं देख रहे हैं।"

9. 24.11.2015 पर शिकायतकर्ता ने धारा 164 Cr.P.C के तहत अपना बयान दर्ज कराया। बयान में शिकायतकर्ता की आयु 47 वर्ष दर्ज की गई थी। बयान में शिकायतकर्ता ने अपने आरोपों को दोहराया।

10. धारा 164 Cr.P.C के तहत बयान दर्ज किए जाने के बाद, आई. ओ. ने शिकायतकर्ता के पति के भाई और उसकी पत्नी के बयान दर्ज करके विस्तृत जांच की। शिकायतकर्ता के साथ, उसके पति का भाई और उसकी पत्नी भी संबंधित समय पर एक ही घर में रह रहे थे। आई. ओ. ने शिकायतकर्ता के पति के भाई निकेश कुमार का बयान दर्ज किया। आई. ओ. द्वारा दर्ज शिकायतकर्ता के पति के भाई के बयान को नीचे निकालना उपयोगी हैः

> "काशा कांत के महलिया विशनपुरा निवासी सुभाष चंद्र विश्नोई के पुत्र श्री निकेश कुमार का वक्तव्य मौजूद है। पूछताछ में कहा गया है कि 22.10.15 पर दशहरा मेला था। मैं अपने बच्चों के साथ मेला देखने गया था और दोपहर 1 बजे अपने घर वापस आ गया था। रेखा रानी मेरी असली भाबी (साली) हैं। अखिलेश और विनीत के बीच पैसे का लेन-देन हुआ है। समय-समय पर मेरे भाई विनीत से चार लाख रुपये उधार लेते थे और उसी राशि को अपने व्यवसाय में लगाते थे और फिर लौट आते थे। अब मौद्रिक लेन-देन के कारण उनके बीच विवाद हो गया है। इस विवाद पर मेरी साली रेखा ने विनीत और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इस तरह के शर्मनाक तथ्यों का उल्लेख करना अच्छा नहीं है और मेरी साली ने अच्छा नहीं किया है। परिवार में छोटे बच्चे हैं और इन तथ्यों का गलत प्रभाव पड़ेगा। मैंने अपने भाई अखिलेश को कोड़ा मारा है और पिता ने भी उन्हें डांटा है। अब वह कह रहे हैं कि गलती हो गई है और जो कुछ भी हुआ है वह हो गया है। मैं और मेरी पत्नी अदालत गए हैं। मुरादाबाद और अदालत में अपना हलफनामा जमा कर दिया है। हमने उसमें सही तथ्य का उल्लेख किया है। हम अदालत में वही तथ्य बताएंगे कि हमारे घर में

ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। मेरी भाबी रेखा ने गुस्से में अदालत में मामला दर्ज कराया है जो कि एक झूठा मामला है।"

11. निकेश कुमार की पत्नी, श्रीमती. बीना विश्नोई ने आई. ओ. के समक्ष निम्नलिखित बयान भी दिया जो केस डायरी का हिस्सा हैः

"श्रीमती बीना विश्नोई का वक्तव्य, महलिया विशनपुरा काशा निवासी बीना विश्नोई पुत्र निकेश कुमार और पी. एस. कांत उपस्थित हैं। पूछताछ करने पर, उसने कहा कि 22.10.15 पर दशहरा उत्सव था और हम दशहरा मेला देखने के बाद वापस आ गए थे और लगभग 5 बजे p.111 पर अपने घर आए थे। मैंने अपनी दुकान खोल ली थी। मेरी एक किराने की दुकान है। अधिकांश लेन-देन शाम को होता है। रेखा मेरी बड़ी असली जेठानी हैं। मेरे जेठ अखिलेश का विनीत और अन्य लोगों के साथ आर्थिक लेन-देन है। वह रुपये उधार लेता था। विनीत से दो लाख, चार लाख अपने व्यवसाय में निवेश करने के लिए और वही रिटर्न। अब मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है और उनके बीच आपसी विवाद पैदा हो गया है और मेरे जेठानी ने ऐसा गलत कदम उठाया है जो हमारे घर में नहीं होता है। हमारा परिवार और विनीत का परिवार महलिया का सम्मानित परिवार है और हमारा लाखों रुपये का व्यवसाय और व्यापार है। हमने उन्हें कोड़ा मारा और डांटा। हमारे बच्चे भी छोटे हो रहे हैं। जब आप लोग जाते हैं तो इसका उन पर प्रभाव पड़ता है। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हमारे घर में बलात्कार आदि की कोई घटना नहीं हुई है और इस संबंध में पूरा महलिया सबूत देगा। मैं अदालत में भी पेश हुआ हूं और एक हलफनामा प्रस्तुत किया है और अदालत में सही तथ्य बताऊंगा।

प्रश्न- 22.10.15 को शाम को 7:30 बजे आप अपने कमरे/दुकान पर मौजूद थे कि क्या आपने कोई चिल्लाहट सुनी है या आपने विनीत को आते या जाते देखा है? उत्तर- 22.10.15 को शाम 5 बजे से हम अपने घर पर थे और हमारे घर में कोई नहीं आया था और रेखा ने हमें सूचित किया है। हमारे घर में बलात्कार की ऐसी कोई घटना नहीं हो सकती थी। आप हमारे सभी पड़ोसियों से पूछताछ कर सकते हैं।"

12. निकेश कुमार और श्रीमती ने भी शपथ पत्र दिए। बीना विश्नोई जो उसी घर में रह रही थीं। श्रीमती. बीना विश्नोई घर के एक हिस्से में जनरल स्टोर की दुकान भी चला रही हैं। उन्होंने कहा कि घटना की तारीख को रेखा रानी दशहरा मनाने के लिए अपने माता-पिता के घर में थीं और अपने घर पर मौजूद नहीं थीं।

13. आई. ओ. जांच पूरी होने के बाद और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री को ध्यान में रखने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाए जाने के अनुसार 22/10/2015 पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई। आई. ओ. द्वारा 29.11.2015 पर अंतिम रिपोर्ट No.40/15 प्रस्तुत की गई थी जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

"उपर्युक्त घटना में प्रथम सूचना रिपोर्ट 6.11.2015 पर दर्ज की गई थी और मेरे द्वारा जाँच शुरू की गई थी। गवाहों के बयान दर्ज करने और घटना स्थल के निरीक्षण के बाद मेरे द्वारा आरोप झूठा पाया गया। इसलिए यह अंतिम रिपोर्ट संख्या 40115 आपके विचार के लिए प्रस्तुत की जा रही है।"

14. 29.11.2015 पर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद पुलिस ने शिकायतकर्ता के खिलाफ धारा 182 Cr.P.C के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए अतिरिक्त मुख्य

न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक और रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने 07.01.2016 दिनांकित विरोध याचिका दायर की। एडिशनल द्वारा इसकी अनुमति दी गई थी। 28.05.2016 पर CJM। उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 482 Cr.P.C के तहत एक आवेदन दायर किया गया था। इसकी अनुमति दी गई और 28.05.2016 दिनांकित आदेश को दरकिनार कर दिया गया जिसमें मजिस्ट्रेट को नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया। मजिस्ट्रेट ने फिर से 03.08.2016 दिनांकित आदेश पारित कर आरोपी को तलब किया। दिनांकित 03.08.2016 आदेश के खिलाफ सत्र न्यायाधीश के समक्ष संशोधन दायर किया गया था जिसे दिनांकित 22.10.2016 आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

15. अभियुक्त ने धारा 482 Cr.P.C के तहत 03.08.2016 दिनांकित आदेश और सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन दायर किया। अभियुक्तों द्वारा यह प्रार्थना की गई थी कि अभिलेखों पर साक्ष्य और सामग्री की सराहना किए बिना आदेश पारित किए गए थे, वे अलग किए जाने के योग्य हैं और विरोध याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां करके आदेशों को रद्द करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दियाः

> "अभिलेख पर सामग्री के अवलोकन और इस स्तर पर मामले के तथ्यों को देखने से यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदकों के खिलाफ कोई अपराध नहीं किया गया है। बार में की गई सभी दलीलें तथ्य के विवाद प्रश्न से संबंधित हैं, जिस पर इस न्यायालय द्वारा धारा 482 Cr.PC के तहत प्रदत्त शक्ति का उपयोग करके निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इस स्तर पर केवल प्रथम दृष्टया मामले को आर. पी. कपूर बनाम आर. पी. कपूर के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में देखा जाना है। पंजाब राज्य, ए. आई.

आर. 1960 एस. सी. 866, हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 एस. सी. सी. (क्र.) 426, बिहार राज्य बनाम। आर. पी. शर्मा, 1992 एस. सी. सी. (सी. आर.) 192 और अंत में ज़ांडू फार्मास्युटिकल्स वर्क्स लिमिटेड। बनाम। मोहम्मद. सरफुल हक और एक अन्य (पार जॉ) 205 एस. सी. सी. (सी. आर.) 283। अभियुक्त के विवादित बचाव पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है।"

16. उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले से व्यथित होकर यह अपील दायर की गई है।

17. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि वर्तमान मामले के तथ्यों में शिकायतकर्ता द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण थी और शिकायतकर्ता, उसके पति और बेटे को उनके द्वारा ली गई राशि का पुनर्भुगतान करने से बचाने के लिए गलत तरीके से शुरू की गई थी, जिसके संबंध में अभियुक्तों द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत पहले ही दायर की जा चुकी थी और लंबित थी। धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत शिकायतकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर मामला दर्ज करने के बाद, आई. ओ. ने शिकायतकर्ता, उसके पति के साथ-साथ पति के भाई और भाई की पत्नी के बयान दर्ज करके पूरी तरह से जांच की। आई. ओ. द्वारा विभिन्न शपथ पत्र भी प्राप्त किए गए थे और जांच करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त सामग्री थी कि कथित बलात्कार की कहानी पूरी तरह से झूठी थी और ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जैसा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था। उन्होंने मामले में एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसे विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए था। यह तर्क दिया जाता है कि आई. ओ. द्वारा एकत्र की गई सामग्री का विज्ञापन किए बिना विरोध याचिका की अनुमति दी गई है। तथ्य यह है कि धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन कथित बलात्कार के 8 दिनों के बाद दायर किया गया था, कथित

बलात्कार को साबित करने के लिए कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, ये शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करने के लिए पर्याप्त थे। इस तरह के गंभीर अपराध के अभियुक्त को समन करना मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में एक यांत्रिक अभ्यास नहीं हो सकता है और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री जो अंतिम रिपोर्ट का हिस्सा थी, उसे अंतिम रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामले में अभियोजन न्यायालय की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है और उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 Cr.P.C के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अलग रखा जाना चाहिए।

18. प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुति का खंडन करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त को बुलाने में निचली अदालतों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, शिकायतकर्ता की धारा 164 Cr.P.C के तहत बयान था जिसमें उसने आरोपी संख्या 1 और 3 द्वारा बलात्कार के अपने मामले को दोहराया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस स्तर पर न्यायालय को साक्ष्य को मार्शल करने और योग्यता के आधार पर आरोप की जांच करने की आवश्यकता नहीं थी और उच्च न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 Cr.P.C के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर दिया है।

19. हमने पक्षों द्वारा की गई दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

20. इससे पहले कि हम वर्तमान मामले के तथ्यों में प्रवेश करें, उच्च न्यायालय में निहित धारा 482 Cr.P.C के तहत अधिकार क्षेत्र के दायरे और दायरे पर विचार करना आवश्यक है। धारा 482 इस संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए या किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा

न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए ऐसे आदेश देने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को बचाती है।

21. इस न्यायालय ने बार-बार धारा 482 Cr.P.C के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता के दायरे की जांच की है और कई सिद्धांतों को निर्धारित किया है जो धारा 482 Cr.P.C के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता के प्रयोग को नियंत्रित करते हैं। कर्नाटक राज्य बनाम एल. मुनिस्वामी और अन्य, 1977 (2) एससीसी 699 में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर कार्यवाही को रद्द करने का अधिकार है कि कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा या न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है कि कार्यवाही को रद्द किया जाना चाहिए। फैसले के पैराग्राफ 7 में निम्नलिखित कहा गया हैः

> "7 ... इस पूर्ण शक्ति के प्रयोग में, उच्च न्यायालय किसी कार्यवाही को रद्द करने का हकदार है यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा या न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है कि कार्यवाही को रद्द किया जाना चाहिए। दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों में उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को बचाना एक हितकारी सार्वजनिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है जो यह है कि अदालत की कार्यवाही को उत्पीड़न या उत्पीड़न के हथियार में बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एक आपराधिक मामले में, एक लंगड़े अभियोजन के पीछे छिपा हुआ उद्देश्य, उस सामग्री की प्रकृति जिस पर अभियोजन की संरचना टिकी हुई है और इसी तरह न्याय के हित में कार्यवाही को रद्द करने में उच्च न्यायालय को उचित

ठहराएगा। न्याय के उद्देश्य केवल कानून के उद्देश्यों से अधिक हैं, हालांकि न्याय को विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार प्रशासित किया जाना है। इन टिप्पणियों को करने के लिए अनिवार्य आवश्यकता यह है कि उस प्रावधान के उद्देश्य और उद्देश्य को उचित रूप से साकार किए बिना, जो राज्य और उसके विषयों के बीच न्याय करने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को बचाने का प्रयास करता है, उस मुख्य अधिकार क्षेत्र की चौड़ाई और रूपरेखा को समझना असंभव होगा।"

22. हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य, 1992 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 335 में इस न्यायालय के फैसले में धारा 482 Cr.P.C के दायरे और दायरे पर विस्तार से विचार किया गया है। हालांकि उपरोक्त मामले में यह न्यायालय एफ. आई. आर. सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति पर विचार कर रहा था, मामला धारा 161,165! पी. सी. और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 (2) के तहत दर्ज एफ. आई. आर. से उत्पन्न हुआ। इस न्यायालय ने आपराधिक जांच में कार्यवाही को रद्द करने के संदर्भ में धारा 482 CR.P.C./अनुच्छेद 226 के दायरे पर विस्तार से विचार किया। इस न्यायालय की विभिन्न पूर्व घोषणाओं को ध्यान में रखने के बाद, इस न्यायालय ने उदाहरण के रूप में मामलों की कुछ श्रेणियों की गणना की, जहां न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग या न्याय के सुरक्षित उद्देश्यों को रोकने के लिए 482. सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। पैराग्राफ 102 जो उन मामलों की 7 श्रेणियों को सूचीबद्ध करता है जहां धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

"102; अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग या संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित निर्णयों की एक

श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों और कानून के सिद्धांतों की व्याख्या की पृष्ठभूमि में, हम निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों को उदाहरण के रूप में देते हैं, जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि यह संभव नहीं हो सकता है कि कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से व्यवस्थित और कठोर दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित किए जाएं और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची दी जाए जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और अन्य सामग्रियों में आरोप, यदि कोई हो, प्राथमिकी के साथ एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराते हैं।

(3) जहां एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए अप्रमाणित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध

के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

(4) जहां, एफ. आई. आर. में आरोप एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहां एक पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है जैसा कि संहिता की धारा 155 (2) के तहत विचार किया गया है।

(5) जहां एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिसके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत एक आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में संस्था और कार्यवाही को जारी रखने और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है, पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट कानूनी बाधा है।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से पेश किया जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसका विरोध करने की दृष्टि से शुरू की जाती है।"

23. कर्नाटक राज्य बनाम एम. देवेंद्रप्पा और एक अन्य, 2002 (3) एस. सी. सी. 89 में तीन-न्यायाधीशों की पीठ को धारा 482 के दायरे पर विचार करने का

अवसर मिला। धारा 482 के दायरे का विश्लेषण करके, इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि न्यायालय का अधिकार न्याय की प्रगति के लिए मौजूद है और यदि उस अधिकार का दुरुपयोग करने का कोई प्रयास किया जाता है ताकि अन्याय पैदा किया जा सके तो न्यायालय के पास दुरुपयोग को रोकने की शक्ति है। इसने आगे कहा कि अदालत किसी भी कार्यवाही को रद्द करना उचित होगा यदि उसे लगता है कि इसकी शुरुआत/निरंतरता अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग या इन कार्यवाही को रद्द करने के बराबर है अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा। पैराग्राफ 6 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

> "6 ..... सभी न्यायालय, चाहे दीवानी हों या आपराधिक, अपने संविधान में निहित किसी भी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में, ऐसी सभी शक्तियां रखते हैं जो न्याय के प्रशासन के दौरान सही करने और गलत को पूर्ववत करने के लिए आवश्यक हैं, इस सिद्धांत पर कि कानून स्वीकार करता है, स्वीकार करता है कि कानून किसी व्यक्ति को कुछ भी देता है जो उसे वह देता है जिसके बिना उसका अस्तित्व नहीं हो सकता है। धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय, न्यायालय अपील या पुनरीक्षण के न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है। धारा के तहत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग हालांकि व्यापक रूप से संयम, सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और केवल तभी जब इस तरह का अभ्यास धारा में विशेष रूप से निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित ठहराया जाता है। इसका प्रयोग वास्तविक और पर्याप्त न्याय करने के लिए किया जाना चाहिए, जिसके प्रशासन के लिए केवल अदालतें मौजूद हैं। न्याय की प्रगति के लिए न्यायालय का अधिकार मौजूद है और यदि उस अधिकार का दुरुपयोग

करने का कोई प्रयास किया जाता है ताकि अन्याय पैदा किया जा सके, तो न्यायालय के पास दुरुपयोग को रोकने की शक्ति है। यह किसी भी कार्रवाई की अनुमति देने के लिए अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा जिसके परिणामस्वरूप अन्याय होगा और न्याय को बढ़ावा देने में बाधा आएगी। शक्तियों का प्रयोग करते हुए अदालत किसी भी कार्यवाही को रद्द करने के लिए उचित होगी यदि उसे लगता है कि इसकी शुरुआत/निरंतरता अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग या इन कार्यवाही को रद्द करने के बराबर है अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा। जब शिकायत द्वारा नए अपराध का खुलासा किया जाता है, तो अदालत तथ्य के प्रश्न की जांच कर सकती है। जब किसी शिकायत को रद्द करने की मांग की जाती है, तो यह आकलन करने के लिए सामग्री को देखने की अनुमति है कि शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाया है और क्या कोई अपराध बनाया गया है, भले ही आरोप पूरी तरह से स्वीकार किए गए हों।"

पैराग्राफ 8 में आगे कहा गया थाः

"8. न्यायिक प्रक्रिया उत्पीड़न या अनावश्यक उत्पीड़न का एक साधन होना चाहिए। न्यायालय को विवेक का प्रयोग करने में चौकस और विवेकपूर्ण होना चाहिए और प्रक्रिया जारी करने से पहले सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा न हो कि यह किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए प्रतिशोध शुरू करने के लिए एक निजी शिकायतकर्ता के हाथों में एक साधन होगा। साथ ही यह धारा किसी अभियुक्त को अभियोजन पक्ष को शॉर्ट-सर्किट करने और उसकी अचानक मृत्यु लाने के लिए

सौंपा गया साधन नहीं है। संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति के प्रयोग का दायरा और उन मामलों की श्रेणियां जहां उच्च न्यायालय किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए संज्ञेय अपराधों से संबंधित अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, इस न्यायालय द्वारा हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल मामले में कुछ विस्तार से निर्धारित किया गया था।"

24. सुंदर बाबू और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य, 2009 (14) एस. सी. सी. 244 में, यह न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने पर विचार कर रहा था, जहां धारा 498ए! पी. सी. और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए आवेदन धारा 482 Cr.P.C के तहत था। इस अदालत के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि दायर की गई शिकायत कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं थी और आरोप निराधार थे। अभियोजन एजेंसी ने धारा 482 Cr.P.C के तहत दायर याचिका का विरोध करते हुए यह रुख अपनाया कि शिकायत के नंगे अवलोकन से कथित अपराधों का खुलासा होता है और इसलिए, यह ऐसा मामला नहीं है जिसकी अनुमति देने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार कर लिया और आवेदन को खारिज कर दिया। इस न्यायालय ने भजन लाल मामले (उपरोक्त) में निर्णय का उल्लेख किया और कहा कि ए मामला श्रेणी 7 के अंतर्गत आता है। श्रेणी 7 पर भरोसा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि धारा 482 के तहत आवेदन को अनुमति दी जानी चाहिए और उसने कार्यवाही को रद्द कर दिया।

25. प्रिया व्रत सिंह और अन्य बनाम श्याम जी सहाय, 2008 (8) एस. सी. सी. 232 के एक अन्य मामले में, इस न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम भजन ला/

(उपर्युक्त) में निर्धारित श्रेणी 7 पर भरोसा किया। उपरोक्त मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 494,120-बी और आई09 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 Cr.P.C के तहत दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया था। धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए पृष्ठभूमि तथ्यों और मापदंडों को ध्यान में रखने के बाद. पैराग्राफ 8 से 12 में निम्नलिखित कहा गया थाः

> "8. इसके अलावा, यह बताया गया है कि दहेज की कथित माँग का आरोप पहली बार दिसंबर 1994 में लगाया गया था। दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दहेज प्रताड़ना 1992 में किसी समय की गई थी। यह नहीं बताया गया है कि दो साल से अधिक समय से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
>
> 9. इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायत याचिका में पति के अलावा, पति की मां, बाद में विवाहित पत्नी, पति की मां की बहन, पति के बहनोई और सुनीता के पिता को पक्षकार के रूप में शामिल किया गया था। पति को छोड़कर किसी को भी विशेष रूप से कोई भूमिका नहीं दी गई है और वह भी फरवरी 1993 में दहेज की मांग की, जब शिकायत 6-12-1994 पर दर्ज की गई थी, यानी लगभग 22 महीनों के बाद। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नोटिस की सेवा के बावजूद, प्रतिवादी 1 की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ है।
>
> 10. इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में धारा 482 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए मापदंड निर्धारित किए गए हैं।

11. "19 यह धारा उच्च न्यायालय को कोई नई शक्ति प्रदान नहीं करती है। यह केवल उस अंतर्निहित शक्ति को बचाता है जो संहिता के अधिनियमन से पहले न्यायालय के पास थी। इसमें तीन परिस्थितियों की परिकल्पना की गई है जिनके तहत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात्, (i) संहिता के तहत एक आदेश को प्रभावी बनाने के लिए, (ii) अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, और (iii) अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए। अंतर्निहित अधिकारिता के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले किसी भी लचीले नियम को निर्धारित करना न तो संभव है और न ही वांछनीय है। प्रक्रिया से संबंधित कोई भी विधायी अधिनियम उन सभी मामलों के लिए प्रावधान नहीं कर सकता है जो संभवतः उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए, न्यायालयों के पास कानून के व्यक्त प्रावधानों के अलावा अंतर्निहित शक्तियां हैं जो कानून द्वारा उन पर लगाए गए कार्यों और कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए आवश्यक हैं। यह वह सिद्धांत है जो उस धारा में अभिव्यक्ति पाता है जो केवल उच्च न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियों को मान्यता देता है और संरक्षित करता है। सभी न्यायालय, चाहे दीवानी हों या आपराधिक, किसी भी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में, जो उनके संविधान में निहित है, ऐसी सभी शक्तियां रखते हैं जो न्याय के प्रशासन के दौरान सही करने और गलत को पूर्ववत करने के लिए आवश्यक हैं। धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय, न्यायालय अपील या पुनरीक्षण के न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है। इस धारा के तहत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग हालांकि व्यापक रूप से संयम, सावधानी और सावधानी के साथ किया

जाना चाहिए और केवल तभी जब इस तरह का प्रयोग धारा में विशेष रूप से निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित ठहराया जाता है। न्याय की प्रगति के लिए न्यायालय का अधिकार मौजूद है और यदि उस अधिकार का दुरुपयोग करने का कोई प्रयास किया जाता है ताकि अन्याय पैदा किया जा सके, तो न्यायालय के पास दुरुपयोग को रोकने की शक्ति है। यह किसी भी कार्रवाई की अनुमति देने के लिए अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा जिसके परिणामस्वरूप अन्याय होगा और न्याय को बढ़ावा देने में बाधा आएगी। शक्तियों का प्रयोग करते हुए अदालत किसी भी कार्यवाही को रद्द करने के लिए उचित होगी यदि उसे लगता है कि इसकी शुरुआत/निरंतरता अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग या इन कार्यवाही को रद्द करने के बराबर है अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा।

20. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के पास बहुत व्यापक शक्तियां हैं और शक्ति की प्रचुरता के लिए इसके प्रयोग में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। न्यायालय को यह देखने के लिए सावधान रहना चाहिए कि इस शक्ति के प्रयोग में उसका निर्णय ठोस सिद्धांतों पर आधारित है। अंतर्निहित शक्ति का उपयोग वैध अभियोजन को दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। किसी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होने के नाते उच्च न्यायालय को आम तौर पर ऐसे मामले में प्रथम दृष्टया निर्णय देने से बचना चाहिए जहां पूरे तथ्य अधूरे और अस्पष्ट हैं, विशेष रूप से तब जब साक्ष्य एकत्र नहीं किए गए हैं और न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गए हैं और इसमें शामिल मुद्दे,

चाहे वे तथ्यात्मक हों या कानूनी, विशाल हैं और उन्हें पर्याप्त सामग्री के बिना उनके सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जा सकता है। बेशक, उन मामलों के संबंध में कोई कठोर और त्वरित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है जिनमें उच्च न्यायालय किसी भी स्तर पर कार्यवाही को रद्द करने के अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा।

[देखें, जनता दल बनाम एच. एस. चौधरी, रघुबीर सरन (डी1:) बनाम बिहार राज्य और मीनू कुमारी बनाम बिहार राज्य, एस. सी. सी. पृष्ठ 366, पैरा 19-20]

12. वर्तमान मामला ऐसा प्रतीत होता है जहाँ हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल में दिए गए चित्रों की श्रेणी 7 स्पष्ट रूप से लागू होती है।"

26. अभिलेखों पर उपलब्ध सामग्री से, 06.11.2015 पर प्राथमिकी दर्ज करने से पहले की घटनाओं के क्रम से निम्नलिखित तथ्यों का खुलासा किया जाता है। शिकायतकर्ता, उसके पति और बेटे ने मई, 2015 के महीने में आरोपी से व्यापार/दुकान के उद्देश्यों के लिए कुल 50 हजार रुपये की अलग-अलग राशि ली थी। गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपरों पर 29.05.2015,01.06.2015 और 31.08.2015 पर तीन समझौते लिखे गए थे जिसमें शिकायतकर्ता, उसके पति और बेटे ने नकद के साथ-साथ चेक द्वारा भी धन की प्राप्ति को स्वीकार किया है। रुपये के चेक। पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अभियुक्तों को 6 लाख, Rs.14 लाख 50 हजार दिए गए। प्रथम बैंक, कांत शाखा, जिला मुरादाबाद में चेक निकाले गए। बैंक में चेक जमा किए गए थे जिन्हें "पर्याप्त शेष राशि नहीं" के समर्थन के साथ वापस कर दिया गया था। चेक का अनादर किए जाने के बाद, शिकायतकर्ता के पति और बेटे के खिलाफ अभियुक्तों द्वारा परक्राम्य लिखत

अधिनियम की धारा 13-8 के तहत शिकायतें दर्ज की गईं जो सितंबर/अक्टूबर के महीने में दर्ज की गई थीं और कथित घटना दिनांक 22.10.2015 से पहले लंबित थीं।

27. शिकायतकर्ता ने आरोपी पर अपने घर पर शाम 7:30 बजे बलात्कार करने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि उसी दिन वह पुलिस स्टेशन गई थी लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। वह बताती है कि एसएसपी को 26.10.2015 पर एक आवेदन भेजने के बाद, उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत एक आवेदन दायर किया। शिकायतकर्ता द्वारा दिनांकित 20.11.2015 की चिकित्सा रिपोर्ट के अलावा कोई चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है। 07.11.2015 पर आई. ओ. जब शिकायतकर्ता से चिकित्सा जांच बी कराने के लिए कहा गया, तो शिकायतकर्ता और उसके पति ने मना कर दिया। यह घटना दिनांक 22.10.2015 को शाम 7:30 बजे हुई थी। शिकायतकर्ता और उसके पति ने 26. 10.2015 तक कुछ नहीं किया जब उसने आरोप लगाया कि आवेदन एस. एस. पी. को भेजा गया था।

28. जाँच के दौरान, आई. ओ. ने शिकायतकर्ता के पति के भाई के साथ-साथ श्रीमती के बयान भी दर्ज किए हैं। पति के भाई की पत्नी बीना विश्नोई, जो एक ही घर में रह रही थीं, ने स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार किया है कि उनके घर में कोई घटना हुई थी। दोनों ने अपने बयानों और हलफनामों में शिकायतकर्ता की झूठी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए निंदा की है।

29. आई. ओ. ने निकेश कुमार और श्रीमती के हलफनामों सहित कई व्यक्तियों के हलफनामे एकत्र किए। बीना विश्नोई और पूरी सामग्री एकत्र करने और घटनास्थल का दौरा करने पर आई. ओ. इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी और उन्होंने दिनांक 29.11.2015 पर एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 29.11.2015 पर

ही, आई. ओ. ने पुलिस को गलत जानकारी देने के लिए धारा 182 Cr.P.C के तहत शिकायतकर्ता पर मुकदमा चलाने के लिए एक और रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

30. अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद. धारा 182 Cr.P.C. दिनांक 29.11.2015 के तहत शिकायतकर्ता ने 07.01.2016 पर विरोध-याचिका दायर की।

31. यह सच है कि धारा 164 Cr.P.C के तहत बयान में शिकायतकर्ता ने अपने आरोप को दोहराया। शिकायतकर्ता ने बयान में अपनी उम्र 47 वर्ष भी दर्ज की है।

32. मजिस्ट्रेट ने विरोध याचिका की अनुमति देने में केवल पैराग्राफ 6 में आरोपी को समन करते समय राज्य द्वारा की गई प्रस्तुति पर विचार किया जो निम्नलिखित प्रभाव से है। :

> "6. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में और साक्ष्य और पूरी केस डायरी के अवलोकन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि शिकायतकर्ता को पुलिस शिकायतकर्ता के रूप में पंजीकृत किया जाना आवश्यक है और आरोपी विनीत कुमार, सोनू और नितेंद्र को भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी, 323 और 352 के तहत उनके मुकदमे के लिए समन करने के लिए पर्याप्त आधार हैं।"

33. विद्वान सत्र न्यायाधीश ने भी धारा 164 Cr.P.C के तहत बयान पर ध्यान देते हुए आदेश की पुष्टि की है।

34. अभिलेख पर यह इंगित करने के लिए पर्याप्त सामग्री थी कि अभियुक्त और शिकायतकर्ता, उसके पति और बेटे के बीच वित्तीय लेनदेन हुए थे। शिकायत के पति और बेटे द्वारा जारी किए गए चेक के अपमान पर अभियुक्त द्वारा परक्राम्य लिखत

अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी गई थी। शिकायतकर्ता के परिवार के सभी सदस्य एक ही घर में रह रहे थे। पति के भाई और उसकी पत्नी ने आई. ओ. के समक्ष अपने बयानों में आरोपी के साथ अपने भाई के वित्तीय लेन-देन को स्वीकार किया है। निकेश कुमार और श्रीमती दोनों के आई. ओ. के समक्ष बयान। बीना विश्नोई को पहले ही ऊपर निकाला जा चुका है, जो केस डायरी का हिस्सा थे और ऐसी सामग्री थी जिस पर गौर किया जाना चाहिए था, जिसे आईओ द्वारा अंतिम रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था

35. तथ्य यह है कि घटना के दिन या अगले दिन या 07.11.2015 पर भी कोई चिकित्सा जांच नहीं की गई थी, जब IO ने शिकायतकर्ता और उसके पति को चिकित्सा जांच करने के लिए कहा था। इसके बाद इसे 20.11.2015 पर किया गया, जो पूरी तरह से अप्रासंगिक था। शिकायतकर्ता के गंजे दावों के अलावा कि सभी अभियुक्तों ने बलात्कार किया है, ऐसा कुछ भी नहीं था जो अदालतों को यह राय बनाने के लिए प्रेरित कर सके कि वर्तमान मामला अभियोजन के मामले के लिए उपयुक्त है जिसे शुरू किया जाना चाहिए। हम इस बात से अवगत हैं कि धारा 164 के तहत अभियोजक/शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए बयान को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन बयान पर पूर्ववृत्तांत, तथ्यों और परिस्थितियों के साथ विचार करने की आवश्यकता थी जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। प्रशांत भारती बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली), 2013 (9) एस. सी. सी. 293 में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक है। उपरोक्त मामले में 21 वर्ष की आयु की शिकायतकर्ता महिला ने दिनांक 1 की घटना के संबंध में आई. पी. सी. की धारा 328 और 354 के तहत एक एफ. आई. आर. दर्ज की। उसने 16.02.2007 पर एक टेलीफोनिक जानकारी भेजी और उसके बयान पर अपीलार्थी के खिलाफ आईपीसी की धारा 328 और 354 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। 21.02.2007 पर पाँच दिनों के

अंतराल के बाद उसने 23.12.2006,25.12.2006 और 01.01.2007 पर अपीलार्थी पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए एक पूरक बयान दिया। अभियोजक की धारा 164 Cr.P.C के तहत बयान दर्ज किया गया था। पुलिस ने आई. पी. सी. की धारा 328,324 और 376 के तहत आरोप पत्र दायर किया. आरोप पत्र में हालांकि उल्लेख किया गया है कि धारा 328/354 के तहत अपराध के समर्थन में कोई सबूत नहीं मिला है। हालाँकि, धारा 164 Cr.P.C के तहत दिए गए बयान के आधार पर आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। आरोप-पत्र को नोट करने वाले फैसले का पैराग्राफ 10 इस प्रकार हैः

> "10 . 28.6.2007 पर, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 328,354 और 376 के तहत आरोप पत्र दायर किया। आरोप-पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि विभिन्न कोणों से पुलिस की जांच का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला था। हालाँकि, आरोप पत्र शिकायतकर्ता/अभियोजक द्वारा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दिए गए बयान पर आधारित था, जो अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ कथित आरोपों के लिए पर्याप्त पाया गया था। उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति को दर्शाने वाले आरोप पत्र का एक प्रासंगिक उद्धरण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा हैः -
>
> "निरीक्षक; बलात्कार के समय पहने गए मादक पदार्थ/पेप्सी/पेप्सी ग्लास और अंडरगारमेंट्स को बरामद करने के लिए सभी कोणों से अपनी पूरी कोशिश की। लेकिन कुछ भी बरामद नहीं हो सका और इस कारण से आरोपी के खून का नमूना एफएसएल को नहीं भेजा जा सका। अब तक की गई जाँच के अनुसार,आई . पी. सी. की धारा

328,354 के तहत अपराध के समर्थन में कोई सबूत नहीं मिला है और यहां तक कि आरोपी प्रशांत भारती की स्थिति भी लोधी कॉलोनी में तारीख और समय पर उपलब्ध नहीं है क्योंकि उसका मोबाइल फोन खराब है। हालाँकि, अभियोजक प्रिया पोरवाल ने 21.2.2007 और 27.2.2007 पर धारा 164 Cr.P.C के तहत बयान दिया जो आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध के लिए उनके चालान के समर्थन में पर्याप्त है।" **जोर दिया गया।**

36. अभियुक्त द्वारा प्राथमिकी को रद्द करने के लिए लिखित याचिका दायर की गई थी जिसे उच्च न्यायालय ने 27.08.2007 पर खारिज कर दिया था। इसके बाद, 01.12.2008 पर आरोप तय किए गए। आरोप तय किए जाने से असंतुष्ट आपराधिक संशोधन याचिका दायर की गई थी जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने 16.01.2009 पर खारिज कर दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का आदेश इस न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 14 में निकाला गया है जो नीचे उद्धृत किया गया हैः

"14. अपने खिलाफ आरोप तय करने में निचली अदालत की कार्रवाई से असंतुष्ट, अपीलार्थी-अभियुक्त ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका नं. 2009 का 08, जिसके तहत उन्होंने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 1.12.2008 के आदेश पर हमला किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए 16.1.2009 पर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दियाः -

"12. आरोपों की सच्चाई या झूठ, अनिवार्य रूप से साक्ष्य के क्षेत्र से संबंधित है और इस प्रारंभिक चरण में इसका पूर्व अनुमान नहीं

लगाया जा सकता है। मुझे विवादित आदेश में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं मिलती हैः नतीजतन, इस संशोधन याचिका को यह स्पष्ट करते हुए सीमित रूप से खारिज कर दिया जाता है कि इसमें कुछ भी परीक्षण के गुण-दोष पर राय के रूप में नहीं माना जाएगा।"

37. अभियुक्त द्वारा उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई थी जिसमें तर्क दिया गया था कि जांच में पर्याप्त सामग्री एकत्र की गई थी जो साबित करती है कि आरोप निराधार थे और अपीलार्थी का अभियोजन अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग था। पैराग्राफ 23 में इस न्यायालय ने कई परिस्थितियों का उल्लेख किया जिनके आधार पर इस न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय की न्यायिक अंतरात्मा को आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए उसे राजी करना चाहिए था। इस अदालत ने आगे ध्यान दिया कि जांच अधिकारी ने स्वीकार किया है कि उन्हें आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है। आरोप पत्र केवल धारा 164 Cr.P.C के तहत शिकायतकर्ता/अभियोजक के बयान के आधार पर दायर किया गया था। फैसले के पैराग्राफ 24 और 25 में निम्नलिखित कहा गया थाः

"24. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपरोक्त आरोपों के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा कोई भी अभिवचन दायर नहीं किया गया है। सुनवाई के दौरान भी, अभियुक्त द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया गया था, उसका खंडन नहीं किया गया था। वास्तव में, शिकायतकर्ता अभियोजक ने स्वयं उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, इस प्रार्थना के साथ कि उसके द्वारा दर्ज की गई पहली जानकारी को रद्द कर दिया जाए। इसलिए इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह निष्कर्ष निकालना वैध होगा कि अभियुक्त द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया गया है, उसका शिकायतकर्ता अभियोजक द्वारा खंडन

नहीं किया गया है। यहां तक कि 28 तारीख के आरोप पत्र में भी। 6.2007, (ऊपर निकाला गया) जाँच अधिकारी ने स्वीकार किया है कि उसे आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है। आरोप पत्र केवल शिकायतकर्ता/अभियोजक के बयान के आधार पर Cr.P.C की धारा 164 के तहत दायर किया गया था।

25. पूर्वगामी दो पैराग्राफ में संक्षेपित तथ्यों और परिस्थितियों के समग्र विचार के आधार पर; हम संतुष्ट हैं कि राज चतुर्थ थापर के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा चित्रित सभी कदम संतुष्ट हैं। सभी चरणों का उत्तर केवल सकारात्मक में दिया जा सकता है। इसलिए हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि उच्च न्यायालय की न्यायिक अंतरात्मा को, उसके समक्ष उपलब्ध सामग्री के आधार पर, विवादित आदेश पारित करते समय, अभियुक्त-अपीलार्थी के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत निहित अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसे राजी करना चाहिए था। तदनुसार, उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर, हम संतुष्ट हैं कि धारा 328 के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट। अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 376 और इसके परिणामस्वरूप 28.06.2007 दिनांकित आरोप पत्र, साथ ही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली द्वारा 01.12.2008 पर आरोप तय करना भी रद्द किए जाने के योग्य है। तदनुसार इन्हें रद्द कर दिया जाता है।"

38. इस प्रकार, उपरोक्त मामला वह था जहां अभियोजक द्वारा धारा 164 के तहत बयान के बावजूद अदालत ने जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री का उल्लेख

करते हुए कहा था कि मामला उपयुक्त था जहां उच्च न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना चाहिए था।

39. धारा 482 Cr.P.C के तहत उच्च न्यायालय को दी गई अंतर्निहित शक्ति न्याय की प्रगति के उद्देश्य और उद्देश्य के साथ है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अप्रत्यक्ष उद्देश्य के साथ न्यायालय की गंभीर प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की कोशिश की जाती है, तो न्यायालय को बहुत हद तक प्रयास को विफल करना होगा। न्यायालय अभियोजन चलाने की अनुमति नहीं दे सकता है यदि मामला हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल में इस न्यायालय द्वारा सचित्र रूप से उल्लिखित श्रेणियों में से किसी एक में आता है। न्यायिक प्रक्रिया एक गंभीर कार्यवाही है जिसे संचालन या उत्पीड़न के साधन में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जब यह इंगित करने के लिए सामग्री है कि एक आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से की जाती है और कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से एक गुप्त उद्देश्य के साथ शुरू की जाती है, तो उच्च न्यायालय हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल में उल्लिखित श्रेणी 7 के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 Cr.P.C के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में संकोच नहीं करेगा, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

> "(7) जहाँ किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से पेश किया जाता है और/या जहाँ कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसका विरोध करने की दृष्टि से शुरू की जाती है।
>
> उपरोक्त श्रेणी 7 वर्तमान मामले के तथ्यों में स्पष्ट रूप से आकर्षित है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल के फैसले को नोट किया है, लेकिन वर्तमान मामले के प्रासंगिक तथ्यों

का विज्ञापन नहीं किया है, जिन सामग्रियों पर आई. ओ. द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस प्रकार, हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि वर्तमान एक उपयुक्त मामला है। उच्च न्यायालय को धारा 482 Cr.P.C के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए था और आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर देना चाहिए था।"

40. परिणामस्वरूप, अपील की अनुमति दी जाती है, उच्च न्यायालय के दिनांकित 16.12.2016 के फैसले के साथ-साथ दिनांकित 03.08.2016 के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश और संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही सहित 22.10.2016 के सत्र न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया जाता है।

अंकित ज्ञान अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक **मनीष शर्मा** द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है,एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।